



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 218] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 31, 1990/भाद्र 9, 1912  
No. 218] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 31, 1990/BHADRA 9, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

वस्त्र संस्थालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 1990

विषय: वर्ष 1991-93 के लिए उन देशों को परिधानों तथा निटवियर के  
संबंध में एम जी एल-3 के अन्तर्गत निर्यात संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत  
जिन देशों में इस प्रकार के निर्यात को मात्रा प्रतिबंध के तहत कर  
किया जाता है।

1. प्रस्तावना।

ग. 1/4/90-ई पी (टी एण्ड जे)-1 (अपेक्स्) :- संयुक्त राष्ट्र अमेरिका  
कनाडा, ई ई सी, आस्ट्रिया, फिनलैंड, स्वीडन तथा नार्वे को सिने सिनाए  
परिधानों और निटवियरों के निर्यात के संबंध में एम जी एल-3 में विहित  
उपबन्धों के अन्तर्गत से वर्ष 1991 से वर्ष 1993 तक के लिए एकवारी  
आबंटन नीति (जिसे इसके बाद आबंटन नीति कहा जाएगा) वह श्रेणी जिसे  
इसके नीचे बताया गया है। किन्तु, आर्वाओ के रुखे दोर के तनीजों  
और एम एल ए. के अविषय के आधार पर आवश्यकतानुसार हम नीति  
में संशोधन का अधिकार सरकार के पास सुरक्षित है।

2. प्रशासन :

(i) जब तक अन्यथा निदेश न दिए जाएं, महानिदेशक, अपेक्स्  
निर्यात संबंधन परिषद, नई दिल्ली ऊनी परिधानों तथा ऐसे एक्नोमिक  
निटवियरों को छोड़कर निर्यात एकवारी का आबंटन करेगा जो ऊन तथा  
ऊनी वस्त्र निर्यात संबंधन परिषद (डब्ल्यू एण्ड डब्ल्यू ई पी सी) के लिए  
समय-समय पर आरक्षित रहेंगे और जिनका आबंटन सचिव, ऊन तथा  
ऊनी वस्त्र निर्यात संबंधन परिषद द्वारा किया जाएगा। किन्तु, महानिदेशक  
अपेक्स् निर्यात संबंधन परिषद इस आबंटन नीति में कवर किय गए ऊनी  
तथा एक्नोमिक निटवियर सहित सभी मिने-सिलाए परिधानों तथा निटवियरों  
के निर्यात के संबंध में आवश्यक प्रमाणपत्र देगा।

(ii) उपरोक्त प्रयोजन के लिए महानिदेशक, अपेक्स् निर्यात संबंधन  
परिषद (ए ई पी सी) सचिव, ऊन तथा ऊनी वस्त्र निर्यात संबंधन परिषद  
(डब्ल्यू एण्ड डब्ल्यू ई पी सी) का अभिप्राय यह होगा और उसमें  
ए ई पी सी तथा डब्ल्यू एण्ड डब्ल्यू ई पी सी के ऐसे अन्य अधिकारी  
शामिल होंगे जिनमें वे ऐसे कार्य तथा उत्तर-दायित्व संभालें: अथवा पूर्णतः  
स्वातंत्र्य अथवा अन्यथा प्रयोजित करें।

(iii) महानिदेशक, ए ई पी सी तथा सचिव, डब्ल्यू एण्ड डब्ल्यू ई पी सी  
उनके द्वारा लागू किसी भी प्रस्थापन के होते हुए भी इस आबंटन  
नीति के क्रियान्वयन के लिए वस्त्र संस्थालय के प्रति उत्तरदायी होंगे।

2353 G/90

(1)

(iv) वस्त्र मंत्रालय द्वारा अधिसूचना के निम्न भाग उपबन्धों के विवेचना के संबंध में प्रतिम प्रधिकारी होगा। वस्त्र मंत्रालय प्रशासन अधिकरणों, उनके कार्यों तथा दायित्वों के संबंध में समय-समय पर ऐसे मासिक मित्थान भी जारी कर सकेगा जैसा वह उचित समझे और वह ऐसे प्राधिकारियों को कार्यों तथा दायित्वों को प्रणत अथवा पूर्णतः पुनः आवंटित कर सकता है, जैसा कि वह उचित समझे।

(v) नियमित हकदारियों का आवंटन केवल उन्हीं नियमितों को किया जाएगा जो आयात नियति नीति के अनुसार सक्षम पंजीकरण प्राधिकारियों के पास पंजीकृत हों।

### 3 आधार अवधि :

किसी वर्ष के लिए "आधार अवधि" कावर्ष इस अधिसूचना में जहाँ कहीं आयात हो, उसका अधिप्राप्त उत दो कैलेंडर वर्षों से होगा जो आवंटन वर्ष से एकवस पहले आये हों। उदाहरणार्थ, वर्ष 1991 के लिए "आधार वर्ष" 1988 तथा 1989 के वर्ष होंगे।

### 4. आवंटन की प्रणाली :

(1) इस अधिसूचना की भाग 5 के अध्वधीन प्रत्येक आवंटन वर्ष में नियति हेतु मात्रा का आवंटन निम्नलिखित प्रणाली के अनुसार उनके सामने विनिर्दिष्ट दरों पर किया जाएगा :

प्रणाली	वार्षिक प्रतिशतता
(क) विगत कार्यनिष्पादन हकदारी (पी पी ई)	60
(ख) पहले आधो पहले पाधो (एफ सी एफ एस)	10
(ग) विनिर्माता नियतक हकदारी (एम ई ई)	18
(घ) सरकारी क्षेत्र हकदारी (पी एस ई)	2
(ङ) गैर-कॉटा नियतक हकदारियाँ (एन वू ई)	10
योग	100

(ii) उपरोक्त के अलावा, अस्पष्टणी लोचणीलताओं, अथवा अन्यथा के परिणामस्वरूप समय-समय पर जो मात्रा उपलब्ध होगी उसका आवंटन भी पहले आधो पहले पाधो की प्रणाली के अन्तर्गत किया जाएगा।

(iii) मांग पैटर्न में परिवर्तनों तथा अन्य सगत कारणों को देखते हुए यदि वास्तविक समझा गया हो उपरोक्त से भिन्न हकदारियाँ आवंटित करने का अधिकार भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय के पास सुरक्षित है।

5. भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय, यह विनिश्चय कर सकता है कि यदि वह उस बात से अनुष्ट है कि पहले आधो पहले पाधो प्रणाली के लिए या तो मूल आवंटन द्वारा अथवा अस्पष्टणी/लोचणीलता, आदि के कारण निर्धारित किसी भी मात्रा को अणत अथवा पूर्णतया किसी ऐसे दूसरी प्रणाली में आवंटित करेगा जैसा कि वह उचित समझे।

### 6 आवंटन

(i) आवंटन का उपयोग करने के लिए वर्ष को पी पी ई, एम ई ई, एन वू ई और पी एस ई के लिए वर्ष को दो अवधियों में बांट दिया जाएगा। पहली अवधि 1 जनवरी से 31 मई तक होगी। दूसरी अवधि 1 जून से 30 सितम्बर तक होगी। कम से कम 50 प्रतिशत आवंटनों को पहली अवधि के दौरान उपयोग किया जाएगा और शेष का दूसरी अवधि के दौरान, किसी भी हकदारी का अप्रयुक्त भाग धारा 14(i) और 16 (iii) के अध्वधीन प्रत्येक अवधि के अन्त में स्वतः ही अप्रयुक्त हो जाएगा।

(ii) उपर्युक्त प्रणालियों में निर्धारित मात्राएं पहली अवधि में चली जायेंगी। ये मात्राएं पहली अवधि को ही जाएँगी और इस कार्य के

लिए महाविशेष, अपेक्षित नियति संशोधन परिपद (पी पी ई, एम ई एस) एवं पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान आवंटनपत्र आमंत्रित कर सकता है।

(iii) एक सी एक एस प्रणाली के तहत सम्पूर्ण मात्रा वर्ष के आरम्भ में उपलब्ध धारा 4(ii) के अध्वधीन ही जाएगी और इस कार्य के लिए महाविशेष, अपेक्षित नियति संशोधन परिपद एवं पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान आवंटनपत्र आमंत्रित कर सकता है।

(iv) वस्त्र आयुक्त निटवीयर, बन्गो के कपड़े, नवी परिधान अथवा किसी अन्य भाग के लिए मात्राएं आवंटित कर सकता है और धारा 13 के प्रावधानों के होते हुए भी ऐसी मात्राओं के लिए अथवा गैरनिम्नतम नीमत घोषित कर सकता है।

### 7. केवल निष्पादन हकदारी (पी पी ई) प्रणाली :

(i) महाविशेष, अपेक्षित नियति संशोधन परिपद निम्नलिखित आश्रय पर पी पी ई का परिकल्पन करेगा।

(ii) उपलब्ध स्तरों का आवंटन आवंटन कर्तारों द्वारा प्रत्येक देश/क्षेत्रों में आधार अवधि के दौरान किये गये नियति के मूल के आधार पर यथानुपात किया जाएगा। तथापि आवंटन को आधार अवधि के दौरान उक्त देश/क्षेत्रों में भारत के वार्षिक औसत निर्यात निष्पादन की सीमा तक परिवर्धित कर दिया जाएगा।

(iii) पी पी ई की मूल वैधता अवधि के दौरान पी पी ई को पूर्णतया या अंशतः हटाने/नियति किया जा सकता है।

(iv) हटाने/नियति पी पी ई (जिसे इसके बाद पी पी टी कहा जाएगा)। उस आवंटन अवधि के लिए वैध होगा, जिसमें हटाने/नियति लागू हुआ है।

(v) पी पी टी की वैधता इसके बाद धारा 14(ii) और 16(iii) में उल्लिखित शर्तों के अध्वधीन बढ़ाई जाएगी।

(vi) पी पी टी के आधार पर गत लक्ष्यों की गणना अन्तर्गणकी द्वारा किये गये नियति के रूप में की जाएगी।

(vii) पी पी टी के अन्तर्गण की अनुमति नहीं है।

### 8. पहले आधो पहले पाधो (एफ सी एफ एस) प्रणाली

(i) आवंटन की तरीका को वैध एवं सी द्वारा समर्पित आवंटनपत्रों पर मात्राएं पहले आधो पहले पाधो के आधार पर आवंटित की जाएगी।

(ii) वस्त्र आयुक्त इस प्रणाली के तहत-प्रतिदिन प्रत्येक देश/क्षेत्रों के लिए प्रत्येक आवंटनकर्ता द्वारा आवंटित की जा सकने वाली अधिकतम मात्रा निर्धारित करेगा। ऐसी अधिकतम मात्रा सामान्यतः प्रत्येक देश/क्षेत्रों के लिए इस प्रणाली के तहत आवंटन के लिए निर्धारित स्तर का 1% होगी। परन्तु जिस मामलों में ऐसे निर्धारित स्तर या तो बहुत कम है या बहुत अधिक है, उन मामलों में यह मात्रा प्रतिवित प्रति आवंटनकर्ता 3000 अथवा से कम या 25000 अथवा से अधिक नहीं होगी।

(iii) इस प्रणाली के तहत आवंटन 60 दिनों की अवधि के लिए वैध होगा, परन्तु धारा 15(ii) के अध्वधीन आवंटन वर्ष के 31 दिसम्बर बाद नहीं।

(iv) आवंटन एक सी एक एस आधार पर दिए जाएँगे और जिस दिन उपलब्ध मात्राओं से सजुरे अधिक जा जाएगी, पावना का निणय उस दिन प्राप्त आवंटन पत्रों में से अधिक उक्त मूल वस्ती के आधार पर किया जाएगा।

(5) एक सी एक एस हटाने/नियति नहीं है।

### 9. विनिर्माता नियतक हकदारी (एम ई ई) प्रणाली

(1) विनिर्माता नियतक की पावना एवं उत्पादन अथवा निर्धारित करने वाला प्राधिकारी वस्त्र आयुक्त होगा;

(ii) इस प्रणाली के तहत आबंटन की पात्रता के लिए विनिर्दिष्ट निर्यातक का न्यूनतम निर्यात निष्पादन उस आभार अवधि के दौरान कम से कम 20 लाख रुपए प्रति वर्ष होना चाहिए, जिसमें उसका उत्पादन एकक दो वर्ष या उसमें अधिक अवधि के लिए अस्तित्व में हो। परन्तु इन दो वर्षों की अवधि के अन्तर जब स्थापित उत्पादन एककों के मामले में न्यूनतम निर्यात निष्पादन की शर्त लागू नहीं होगी।

(iii) एम.ई.ई. के तहत आबंटन की पात्रता के लिए किसी निर्यातक के संबंध में मिलाई मशीनों और कामगारों के अनुसार न्यूनतम श्रमता का निर्धारण वस्त्र आयुक्त करेगा। संबंधित श्रमता का निर्धारण करते समय वस्त्र आयुक्त अन्य संस्थापित मशीनों का भी समुचित महत्व देगा। वस्त्र आयुक्त कामगारों की संख्या और संस्थापित मशीनों के बीच उचित सह-संबंधों के प्रति भी स्वयं संतुष्ट होगा।

(iv) एम.ई.ई. के तहत केवल विनिर्माता निर्यातक की पंजरी में निर्दिष्ट माल के संदर्भ में आबंटन होता है। अर्थात्, जिसमें लीज में ली गई फैक्ट्रियां शामिल हैं, विनिर्माता माल एम.ई.ई. के लिए आवेदन नहीं होगा।

(v) उपलब्ध मात्रा का वितरण महानिदेशक, अपरेटिव निर्यात संबंधित परिषद् द्वारा आवेदनकर्ताओं की ऐसी उत्पादन श्रमता के आभार पर यथानुपात किया जाएगा जिसका निर्णय वस्त्र आयुक्त द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक आवेदनकर्ता उसके आवेदन के लिए अधिकतम पांद्रह देश/क्षेत्रों चुन सकता है।

(vi) जब यह देखा जाएगा कि एक देश/क्षेत्र के लिए एक या अधिक विनिर्माता-निर्यातक को आवंटित मात्रा बहुत थोड़ी है (वस्तु आयुक्त द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार), तब महानिदेशक अपरेटिव निर्यात संबंधित परिषद् इन मात्राओं को इस तरीके से पुनः आवंटित करेगा कि प्रत्येक आवेदनकर्ता को आवंटित मात्रा काफी व्यापक हो सके।

(vii) किसी विनिर्माता निर्यातक के लिए, जिसकी पीपीई. के अंतर्गत भी हकदारी है, पीपीई. और एम.ई.ई. के तहत कुल आवंटन की मात्रा आधार अवधि के दौरान उसके द्वारा निर्यातित मर्च की वार्षिक औसत में के 125% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

\*उपयुक्त अवधि में उनके द्वारा वसूल किया गया घुटित मूल्य

उपयुक्त अवधि में भारत द्वारा वसूल किया गया औसत घुटित मूल्य।

नए एम.ई.ई. धारकों को आवंटित मात्रा मौजूद पीपीई. धारकों को एम.ई.ई. के अंतर्गत आवंटित मात्राओं के समान हो होगी।

(viii) एम.ई.ई. अंतरांतरणीय है। किसी विशेष वर्ष में एक घुटित को एम.ई.ई. के आवंटन से पहले मालिक/प्रबंध साझेदार/प्रबंध निदेशक को इस उद्देश्य का शपथपत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए कि (क) पिछले वर्ष के दौरान प्रयुक्त की गई एम.ई.ई. यदि कोई हो, का प्रयोग उन्हीं वस्तुओं के निर्माण के लिए किया गया है जिनके लिए उनके स्वामित्व वाले घुटितों को एम.ई.ई. का आवंटन किया गया हो (ख) वास्तव में उनके स्वामित्व वाले घुटितों में अब उनकी आवंटित की जाने वाली उनकी हकदारी के लिए वह वस्तुओं का निर्यात करेगा। प्रमाणीकरण आवेदनपत्र के साथ वह इस आशय का एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा कि इस समय निर्यात की जा रही वस्तुओं का निर्यात उन्हीं घुटितों में हुआ है।

(ix) यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस प्रणाली के तहत आबंटन प्रणाली निमाताओं द्वारा प्राप्त किए जाते हैं संस्थापित श्रमताओं की जांच की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, वस्त्र आयुक्त इस प्रणाली के अंतर्गत आबंटन में पात्र आवेदकों के सभी घुटितों का नीति अवधि के दौरान कम से कम एक बार अधिकाधिकियों के दल से निरीक्षण करवाएंगे। नए एकक जो इस प्रणाली के अंतर्गत आबंटन में पहले दो वर्षों के भीतर स्थापित किए गए हैं, का प्रत्यक्षता के आधार पर निरीक्षण किया जाना चाहिए।

(x) इस प्रणाली के अंतर्गत किए गए आवंटन के तहत लिये गये निर्यातों के मामले में लागू निम्नतम निर्धारित कीमतों (फ्लोर प्राइसेस)

वस्त्र आयुक्त द्वारा घोषित सामान्य निम्नतम निर्धारित कीमतों से 10 प्रतिशत अधिक होंगे।

10. सरकारी और हकदारी (पी.एम.ई.) प्रणाली

(i) केन्द्रीय/राज्य सरकारों और केन्द्रीय/राज्य स्तर की शीर्ष महकारी समितियों के नियंत्रणाधीन निगमों के लिए 2% का आबंटन होगा।

(ii) इस प्रणाली के अंतर्गत आबंटनों के लिए निगम/महकारी समिति की पात्रता के लिए मापदंड वही होगा जैसा कि उपर्युक्त खंड 9 में दिया गया है। आबंटन की क्रियाविधि वही होगी जो एम.ई.ई. प्रणालियों के लिए बिहा है।

(iii) विनिर्माण ब्रिजाकाय को इस प्रकार के जी.एम.ई. धारक के प्राधिकृत क्षेत्रों तक भौगोलिक दृष्टि से सीमित करना होगा।

11. गैर-कोटा हकदारी प्रणाली

(i) गैर कोटा देशों को परिधानों तथा कोटा देशों को गैर-कोटा मर्चों के निर्यातक इस प्रणाली के तहत पात्र नहीं होंगे बल्कि भूमिगत फीकरेसी में किया गया हो और निर्यातक का आधार अवधि के दौरान कम से कम 30 लाख रु. का निर्यात निष्पादन हुआ हो। इस स्तर का 50% भाग आठ देशों की किये जाने वाले निर्यात के लिए आरक्षित होगा। आठ देश होंगे जापान, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, मैक्सिको, अर्जेंटीना और पेरू।

(ii) इस प्रणाली के अंतर्गत आधार अवधि के दौरान हकदारी निर्यात के मूल्य के आधार पर परिकल्पित की जाएगी और उपलब्ध स्तर प्रत्यक्ष-प्रत्यक्ष आवेदकों के निर्यात के मूल्य के आधार पर यथानुपात वितरित किये जाएंगे।

(iii) आवेदन के लिए किसी निर्यातक को 15 देशों/क्षेत्रों के समूह का चयन करने की अनुमति दी जाएगी।

(iv) एक विशेष होल्ड स्तर होगा जिससे निर्यातक को आवंटित किया जाएगा जैसा कि एम.ई.ई. के मामले में होता है।

(v) पीपीई. की अवधि तक लागू शर्तें एन.क्यू.ई. को भी लागू होंगी।

(vi) एन.क्यू.ई. हस्तांतरणीय है जिसका (इसके बाद में एन.क्यू.टी. के रूप में उल्लेख किया जाएगा) और अंतरण की शर्तें वही होंगी जो पीपीई. के मामले में हैं। एन.क्यू.टी. हस्तांतरणीय नहीं है।

12. कम व्यापार वाली मर्चें

(i) वह वस्तु कम व्यापार वाली घोषित की जाएगी यदि प्रत्येक आधार अवधि में उसका उपयोग सगन वर्षों में आधार स्तर के 75% से कम हो। महानिदेशक ए.ई.पी.सी. अधिक से अधिक पिछले वर्ष के एक दिसंबर तक कम व्यापार वाली वस्तुओं के रूप में घोषित करेंगे।

(ii) इस अभिसूचना के किसी भी उपबंध में दी गई किसी अन्य बात के होते हुए कम व्यापार वाली वस्तुओं के लिए निम्नलिखित सूट दी जाएगी:

(क) एफ. सी. एफ. एस. के तहत अनिवार्य शाखपत्र के लिए कोई अनुबंध नहीं होगा।

(ख) उपर्युक्त पैरा 8 द्वारा एक्सोएफ़स के लिए अनुबंधित मात्रात्मक सीमा लागू नहीं होगी।

(iii) उपर्युक्त ग्राहकों में से किसी को भी चालू मांग पैटर्न के आधार पर वस्त्र आयुक्त द्वारा बिना अधिसूचना दिए वापस लिया जा सकता है।

13. न्यूनतम कीमतें:

(i) वस्त्र आयुक्त द्वारा प्रत्येक देश/क्षेत्र के लिए सामान्यतया एक ही न्यूनतम कीमत निर्धारित की जाएगी।

(ii) न्यूनतम कीमत निर्धारित करने समय आधार अवधि के दौरान वसूल किया घुटित मूल्य और निर्धारित दर में उतार-चढ़ाव को भी ध्यान में रखा जाएगा।

14. नौबहन बिल के संघ में प्रमाणिकरण की वैधता अवधि :—

(i) नौबहन बिल पर महानिदेशक, ए. ई. पी. सी. द्वारा प्रमाणिकरण की वैधता अवधि बही होगी जो सगन हकदारी की वैधता की अवधि होगी।

(ii) आवंटन की सभी प्रणालियों में प्रमाणिकरण की वैधता में 30 दिन की समायावधि वृद्धि, एक ओबी मूल्य का 15 प्रतिशत का अतिरिक्त ई.एम.डी/बी.जी. ए. ई. पी. सी. को प्रस्तुत करके अगले 30 दिनों के लिए, अगले 15% का और अतिरिक्त ई.एम.डी/बी.जी. द्वारा प्राप्त की जा सकती है और वह हर हालत में 31 दिसंबर से अधिक नहीं होगी।

(iii) महानिदेशक, ए. ई. पी. सी. इस प्रकार की समय वृद्धियाँ देते के लिए सक्षम होगा।

(iv) उपर्युक्त के अतिरिक्त और कोई वृद्धियाँ नहीं दी जाएंगी।

#### 15. हथकरघा परिधान

हथकरघा परिधानों के लिए आरक्षित विशेष मामलों का आवंटन कुछ देशों के लिए 90 : 10 के आधार पर एक सी एक एस और पी एस ई के तहत किया जाएगा।

16. ई.एम.डी/बी.जी. अवधर्नन :

(i) पीपीई, एम.ईई, एनक्यूई और पी.एस.ई. प्रणालियों के मामले में हकदारी की मूल वैधता अवधि के दौरान ई.एम.डी/बी.जी. प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(ii) एक सी एक एस प्रणाली के मामले में निर्यातकों आवेदन माताओं पर एक ओबी मूल्य के 5% की दर से ई.एम.डी/बी.जी. देना आवश्यक होगा।

(iii) ई.पी.ई., एम.ईई, एनक्यूई और पी.एस.ई. की वैधता मामूल्याता: अंश 6(1) के अनुसार होगी। तथापि, पी.पी.टी. और एनक्यू.टी. सहित उपर्युक्त प्रणालियों में दूसरी अवधि के लिए निर्धारित की गई माता की वैधता को एक ओबी मूल्य के 20% की दर से ई.एम.डी/बी.जी. के साथ कृण पत्र के लिए 31 दिसंबर तक बढ़ाया जा सकता है।

(iv) जो निर्यातक एक सी एक एस पाटी, एनक्यू.टी. के प्रत्येक किसी विशेष अवधि में, या पी.पी.टी., एम.ईई/एनक्यू.टी. या पी.एस.ई. को मिलाकर एनक्यू.ई. सहित पी.पी.टी. के लिए उपयुक्त पैरा (3) में निर्धारित पुनर्विधेकरण अवधि के दौरान निर्यात हकदारों के 95% से कम निर्यात करता है, तो जैसे कि शर्त है, इसके बाद उसको ई.एम.डी/बी.जी. अंक हो जाएगा। उपयोगिता गैरिस्ट के अनुपात में अधिक कारोबार वाला मर्चों के मामले में 75% तथा कम कारोबार वाला मर्चों के मामलों में 50% तक उपयोग के मामले में डा.जा.ए.ई.वा.मा. ई.एम.डी/बी.जी. को अंक कर लेगा। यदि निर्यात हकदारा आवंटन का उपयोग उपर्युक्त से कम है तो, ई.एम.डी/बी.जी. पूर्ण होना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए उपयोगिकरण का प्रत्येक अवधि के लिए और प्रत्येक प्रणाली के आधार पर अलग-अलग परिकल्पित किया जाएगा। वैधता प्रमाणन की अवधि बढ़ाने के मामले में उपयोग का प्रतिशत प्रत्येक बढ़ाई गई प्रमाणन वैधता के लिए अलग-अलग परिकल्पित किया जाएगा।

(v) सभी जहाँ ई.एम.डी/बी.जी. को सरकार के पी.डी. खातों में जमा कर दिया जाएगा और उसका प्रचालन इस प्रकार होगा जैसा सरकार समय-समय पर अधिभूजित करे।

(vi) वे व्यक्ति जिन्होंने निर्यात हकदारों या आवंटन को जोते हैं परन्तु जो उनका पूर्णतया उपयोग नहीं करते हैं, ता उनका खिमाफ खतरनी किसी कारणवश के संबंध में दिया गयी पूर्वावधि के अधीन में

हकदारी प्राप्त करने के लिए प्रयत्न हो जाने के लिए उत्तरदायी होंगे।

(vii) समय वृद्धि के लिए सभी तरह से पूर्ण आवेदन पत्र मूल हकदारी की वैधता अवधि समाप्त होने से पहले जमा कर दिए जायेंगे।

17. ई.एम.डी/बी.जी. को जहाँ के लिए एक अवधि :

उपर पैरा (16)(iv) के अंतर्गत डा.जी. ए.ई.पी.सी. द्वारा जहाँ के आदेश में प्रभावित कोई भी निर्यातक, जहाँ पत्राचार प्राप्त होने के 15 दिनों के अन्दर अम्बर एम्बर अन्तों के खिलाफ बख्त आयुक्त, बम्बई के समक्ष अपील कर सकता है। बख्त आयुक्त अध्यावेदन प्राप्त करने के पश्चात् यथा नीचे एक निर्णय आदेश देगा। अपीलों का निराकरण करते समय प्रभावित प्रमुख शर्तों का ध्यान में रखा जायेगा। वह हकदारों की वैधता के दौरान उपयोग न की गयी हकदारियों का मौपने में तत्परता पर भी विचार करेंगे। इस उद्देश्य के लिए वह आयुक्त स्वयं द्वारा मनोनीत अधिकारियों को शामिल कर सकता है, और उन्हें सहाय्य बना सकते हैं।

18. सामाजिक द्वारा विपक्षित्व

(क) समुक्त राज्य अमेरिका में विषय सामग्री के अंतर्गत न आने वाली मर्चों सहित समाप्ति प्रतिबंधाधीन उत्पाद। पोतलवान, पत्तर पर मानाशुल्क प्रतिकारियों द्वारा पोतलवान की अनुमति, मूल रूप में निर्यात हकदारों प्रमाणन और अलग-अलग व्योह के लिए ए.ई.पी.सी. द्वारा जारी की गई परिचयन पत्रों के अनुरोध के मत्वापन के साथ हो दो जाएंगे।

(ख) हथकरघा परिधान

मिली हुई कॉलरदार कमाज जो काशा में प्रविष्टि न द हैं, आस्ट्रिया का सूती हथकरघा परिधान, यू.ए., ई.ई.पी.सी., फिलिपिन्स में कुछ प्रतिबंधित श्रेणियों के हथकरघा परिधानों के लिए आरक्षित विशेष माता को छोड़कर सभी हथकरघा वस्त्रों के निर्यात के लिए पोतलवान की अनुमति सामाजिक अधिकारी वास्कीनेशन फार्म के पैरा 2 में वर्तमान समिति द्वारा निराकरण सूचना के आधार पर देगे।

भारतीय मर्चों के अंतर्गत आने वाले परिधान

भारतीय मर्चों, जो भारत के परम्परागत लोकराजि के हाथीरूप बख्त उत्पाद हैं, के सम्बन्ध में ई.ई.पी.सी., यू.ए., फिलिपिन्स, आस्ट्रिया, स्वीडन, नार्वे और कनाडा के निर्यात के लिए पोतलवान की अनुमति सामाजिक अधिकारी विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के कार्यालय द्वारा जारी उपर्युक्त प्रमाणपत्रों के अधीन पर देंगे।

(क) निर्यात प्रमाणपत्र, उद्गम प्रमाणपत्र और रीमा :—

सगल द्विपक्षीय बख्त करारों के अंतर्गत अपेक्षित निम्नांकित प्रमाणपत्र ए.ई.पी.सी. या उसकी ओर से विधिवत प्राधिकृत अन्य एजेंसी द्वारा जारी किए जायेंगे।

(1) ई.ई.पी.सी.

(क) प्रतिबंधाधीन सभी परिधानों/निर्दिष्ट मर्चों के लिए निर्यात प्रमाणपत्र और उद्गम प्रमाणपत्र।

(ख) सभी गैर प्रतिबंधित परिधानों/निर्दिष्ट मर्चों के लिए उद्गम प्रमाणपत्र।

(2) फिलिपिन्स

प्रतिबंधित मर्चों के लिए निर्यात प्रमाणपत्र।

(3) आस्ट्रिया

प्रतिबंधित मर्चों के लिए निर्यात प्रमाणपत्र।



- (4) आस्ट्रिया प्रतिबंधित निर्यातों के अर्धन परिधानों के लिए निर्यात प्रमाणपत्र।
- (5) नावे विशेष सोमाओं के अध्यादेश श्रेणियों के बारे में निर्यात प्रमाणपत्र और उद्भव प्रमाणपत्र।
- (6) कनाडा निट्रेड, पावरलूम और निट्रेड उद्भव वाले परिधानों के लिए निर्यात प्रमाणपत्र। 500 कैंडियन डॉलर या कम मूल्य का खेप को छोड़कर, जेब प्रमाणपत्र है।
- (7) यू.एस.ए. 250 अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य का खेप वाले नए परिधान निर्यात के लिए कनाडा।

## (ख) हथकरघा प्रमाणपत्र

कनाडा में प्रतिबंधित मर किमोनो सिलाई काल्स्टर कर्माज, आस्ट्रिया के लिए सूता कथकरघा परिधान तथा ईईसी, नावे और फिनलैंड में कुछ प्रतिबंधित श्रेणियों में हथकरघा परिधानों के लिए आरक्षित विशेष मात्राओं को छोड़कर सभी हथकरघा परिधानों के निर्यात के बारे में वस्त्र समिति ऐसे उत्पादों के लिए द्विपक्षीय करारों में निर्धारित प्रमाणपत्र जारी करेगी।

20. सरकार को किसी भी पूर्ववर्ती प्रावधान में बिना किसी सूचना के संशोधन करने का अधिकार होगा।

भा. शंकर, संयुक्त सचिव,  
वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली

## MINISTRY OF TEXTILES NOTIFICATION

New Delhi, the 31st August, 1990

Subject:—Guidelines for Export under OGL-3 in respect of garments and knitwear to countries where such exports are covered under quantitative restraints for the calendar year's 1991-93.

### 1. Introduction :

No. 1/4/90 -EP(T&J)1 (Apparels).—Pursuant to provisions contained in OGL-3 in respect of export of readymade garments and knitwear to USA, Canada, EEC, Austria, Finland, Sweden and Norway, the Policy for Allotment of Entitlements (hereinafter referred to as the Allotment Policy) for the year 1991 to 1993 shall be as hereinafter detailed. However, depending upon the outcome of the Uruguay Round of Negotiations and the future of MFA, Government reserves the right to amend the policy as necessary.

### 2. Administration :

(i) Unless otherwise directed, the Director General Apparels Export Promotion Council, New Delhi shall allocate export entitlement except for woollen apparels and such acrylic knitwears reserved from time to time for W&WEPC where allocation shall be made by the Secretary W&WEPC. However DG, AEPC shall do the necessary certification for all export of readymade garments and knitwear includ-

ing woollen and acrylic knitwear covered in this Allotment Policy.

(ii) For the purpose of the above, the Director General of AEPC and W&WEPC shall mean and include such other officials of AEPC and W&WEPC to whom they expressly or otherwise delegate part or whole of such functions and responsibilities.

(iii) The Director General, AEPC and the Secretary, W&WEPC notwithstanding any delegations effected by them shall be accountable to the Ministry of Textiles for implementation of the allotment policy.

(iv) The Ministry of Textiles shall be the final authority regarding interpretation of any of the provisions of this notification. The Ministry of Textiles may also issue such guidelines as it deems fit from time to time regarding agencies of administration, their functions and responsibilities and may reallocate part or whole of the functions and responsibilities to such authorities as it deems fit.

(v) Export entitlements will be allotted only to exporters registered with the competent registering authorities as per Import-Export Policy.

### 3. Base Period :

The phrase "base period" for an allotment year, wherever appearing in this notification, shall mean the two calendar years preceding the year immediately before that allotment year. For example, the "base period" for the year 1991 shall be the years 1988 and 1989.

### 4. Systems of Allotment :

(i) Subject to clause 5 of this notification, quantities for export in each allotment year shall be allocated according to the following systems at rates indicated against each of them:—

System	Percentage of Annual level
(a) Past Performance Entitlement (PPE)	60
(b) First-come-First served (FCFS)	10
(c) Manufacturer Exporter Entitlement (MEE)	18
(d) Public Sector Entitlement (PSE)	2
(e) Non quota Exporters Entitlements (NQE)	10
Total	100
(b) First-come-First served	10

(ii) Apart from the above, quantities that become available from time to time on account of surrenders, flexibilities or otherwise shall also be allocated under FCFS system.

(iii) Government of India in the Ministry of Textiles reserves the right to allocate entitlements in variation with the above in case if is considered so desirable, in view of changes in demand pattern and other relevant consideration.

5. Government of India in the Ministry of Textiles may decide, if so satisfied, that part or whole of any of the quantities earmarked for FCFS either by way of original allocation or on account of surrender/flexibilities etc. shall be allotted in such other manner as it deems fit.

#### 6. Allotments :

(i) For the purpose of utilisation of allotment the year shall be divided into two periods for PPE, MEE, NQE and PSE. The first period shall be from 1st January to 31st May. The second period shall be from 1st June to 30th Sept. A minimum of 50 per cent of the allotments for the year should be utilised during the first period and the balance during the second period. The unutilised portion of any entitlement shall stand automatically surrendered at the end of each period subject to clause 14(ii) and 16(iii).

(ii) The quantities earmarked in the above systems shall be released in the first period. The quantities shall be opened on 1st January and for this purpose DG, AEPC may invite applications during the previous year.

(iii) The entire quantity under FCFS system shall be opened at the beginning of the year (subject to clause 4(ii) above) and for this purpose DG, AEPC may invite applications during the previous year.

(iv) Textiles Commission may reserve quantities for knitwear, children's wear, woollen garments, or any other segment and may announce separate floor prices for such quantities notwithstanding the provisions in clause 13(i).

#### 7. Past Performance Entitlement (PPE) System :

(i) The DG, AEPC shall compute PPE on the following basis.

(ii) Available levels will be allotted pro-rata on the basis of the value of exports during the base period by the applicants in each country/category. Allotments, however, will be restricted to the annual average export performance of India in the country/category during the base period.

(iii) PPE shall be transferable, either in full or in part, during the period of original validity of the PPE.

(iv) A transferred PPE (hereinafter referred to as PPT) shall be valid for the allotment period in which the transfer is effected.

(v) Extension of validity of PPT shall be subject to conditions enumerated hereinafter at Clause 14(ii) and 16(iii).

(vi) Shipments against PPT will be counted as exports by the transferee.

(vii) Transfer of a PPT is not allowed.

#### 8. First-Come-First-Served-FCFS) System :

(i) Quantities shall be allocated on First-Come-First-Served basis against applications supported by L.C.s valid on the date of application.

(ii) Textile Commissioner will fix the maximum quantity that can be applied by any applicant for each country/category under this system per day. Such maximum quantity will be ordinarily 1% of the level earmarked for allocation under this system for each country/category. However, in cases where such earmarked levels are either too low or too high, the quantity in such cases will not be less than 3,000 pieces or more than 25,000 pcs per applicant per day.

(iii) Allotment under this system shall be valid for a period of 60 days, but not beyond 31st December of the allotment year subject to clause 14(ii).

(iv) Allotments shall be granted on FCFS basis, and on a day when available quantities are over-subscribed, eligibility shall be decided on the basis of higher unit value realisation among the applications received on the day.

(v) FCFS is not transferable.

#### 9. Manufacturer Exporter Entitlement ( MEE) System;

(i) The Textile Commissioner shall be the authority for deciding the eligibility and production capacity of a Manufacturer Exporter.

(ii) For Manufacturer-Exporter to be eligible for allotment under this System, he shall have a minimum export performance of at least Rs. 20 lakhs per year during the base period, where his production unit has been in existence for two years or more. However, in the case of production units newly established within this period of two years, the condition of minimum export performance shall not be enforced.

(iii) The Textile Commissioner shall prescribe the minimum capacity in terms of sewing machines and workers for an exporter to be eligible for allotment under MEE. While assessing relative capacity, Textile Commissioner shall also give due weightage to other machines installed. The Textile Commissioner will also satisfy himself about a reasonable correlation between the number of workers and machines installed.

(iv) The allotment under MEE is in respect of goods manufactured in the factory of the owner only. Goods manufactured elsewhere including factories under leasehold shall not be eligible for MEE.

(v) Available quantities will be distributed by DG, AEPC pro-rata on the basis of production capacity of eligible applicants as decided by the Textiles Commissioner. Each applicant may opt for a maximum of fifteen country/categories for the above allotment.

(vi) When it is observed that quantity allotted to one or more of Manufacturer-Exporters for a country category is too small (as decided by Textile Commissioner) the D.G., AEPC shall reallocate these quantities in such a manner that the quantity allotted to each of the applicants is reasonable enough.

(vii) The total allocation under PPE and MEE for a Manufacturer Exporter who also has entitlements under PPE shall not exceed 125% of Annual Average no. of pieces exported by him during the base period\*.

\* Unit value realised by him in the above period

Avg. unit value realised by India in the above period  
The quantity allotted to new MEE holder shall be equitable with the quantities allotted under MEE to existing RPE holders.

(viii) MEE is not transferable. Before allocation of MEE to a unit in particular year, the Proprietor/Managing Partner/Managing Director shall be asked to submit an affidavit to the effect that (a) the MEE utilised during the previous year, if any, was for goods physically manufactured by the units owned by him against which the MEE had been allotted and (b) he shall manufacture the goods for entitlement to be allotted now to him in units physically owned by him. Along with the certification application, he shall submit an affidavit that the goods presently being exported have been manufactured in the same units.

(ix) In order to ensure that allotments under this system are availed by genuine manufacturers the Textile Commissioner shall cause all the units of applicants held eligible for allotment under this system inspected by a team of officers at least once during the policy period, with a view to verifying the installed capacities. New unit i.e. those set up within two years prior to the allotment under this system, shall be inspected on a priority basis.

(x) In the case of exports against allotments under this system, the floor prices applicable will be 10% higher than general floor prices announced by the Textile Commissioner.

#### 10. Public Sector Entitlement (PSF) System :

(i) For Corporations under the control of Central/State Govts. and Apex Cooperatives of Central/State level, there shall be an allocation of 2%.

(ii) The criteria for eligibility of a Corporation/Cooperative for allotments under this system would be the same as stipulated in clause 9 above. The procedure for allotment will also be the same as stipulated for MEE systems. PSE is not transferable.

(iii) The manufacturing activity shall have to be geographically limited to the authorised areas of operation of such PSE holder.

#### 11. Non-Quota Entitlement System :

(i) Exporters of apparels to Non-quota countries and non-quota items to quota countries shall be eligible under this system provided the payment is

received in free currency, and the exporter has a minimum export performance of Rs. 30 lacs during the base period. 50% of this level be reserved for exports to thrust countries viz., Japan, Australia, New Zealand, Switzerland, Mexico, Brazil, Argentina, Peru.

(ii) Entitlement under this system shall be calculated on the basis of value of exports during base period and the levels available will be distributed pro-rata on the basis of the value of exports of individual applicants.

(iii) An exporter shall be permitted a choice of 15 countries/categories combination for allotment.

(iv) There shall be a threshold level that can be allotted to an exporter, as in the case of MEE.

(v) Conditions applicable to PPE so far as may be shall be applicable for NOE also.

(vi) NOE is transferable (hereinafter referred to as NOT) and the conditions of transfer shall be same as in case of PPE. NOT is not transferable.

#### 12. Slow moving items :

(i) An item shall be declared to be slow-moving if during each of the years of the base period, its utilisation has been less than 75% of the base level for the corresponding years. The Director General, AEPC shall declare the items that are slow moving latest by 1st December of the previous year.

(ii) Notwithstanding anything else contained in any of the provisions of this notification, the following relaxations shall ordinarily be available for a slow-moving items :—

(a) There shall be no stipulation for compulsory Letter of Credit under FCFS.

(b) The exporter will have to furnish 1% EMD/BG instead of the rates stipulated for other categories under FCFS.

(c) The quantitative ceiling stipulated for FCFS vide para 8 above shall not be enforced.

(iii) Any of the above relaxations may be withdrawn without advance notice by the Textiles Commissioner on the basis of current demand pattern.

#### 13. Floor Prices :

(i) Ordinarily there shall be only one floor price for each country/category to be fixed by the Textiles Commissioner.

(ii) While fixing floor price, the average unit value realisation during the base period and the fluctuation in exchange rate shall be taken into consideration.

#### 14. Validity Period of Certification on Shipping Bill :

(i) The validity period of a certification by DG, AEPC on a shipping bill shall be the same as the validity of the relevant entitlement.

(ii) In all systems of allotment extension of the validity period of certification can be obtained for 30 days by furnishing to AEPC an additional EMD/BG of 15 per cent of the F.O.B. value; and for another



30 days by further additional EMD/BG of 15 per cent and in any case not beyond 31st December.

(iii) The DG, AEPC shall be competent to grant such extensions.

(iv) There shall be no extensions save as provided above.

#### 15. Handloom Garments :

Special quantities reserved for handloom garments for certain countries will be allotted under FCFS and PSE on 90 : 10 basis.

#### 16. EMD/BG Forfeiture :

(i) In case of FPE, MEE, NOE and PSE systems, exporters will not be required to furnish EMD/BG during the original validity of the entitlement.

(ii) In case of FCFS system, an exporter shall be required to give EMD/BG at the rate of 5 per cent of the F.O.B. value on the quantities applied for.

(iii) The validity of PPE, MEE, NOE and PSE shall be normally as per clause 6(i). Validity of the quantity earmarked for the second period, in the above systems including PPT and NQT however, can be extended upto 31st December against Letter of Credit accompanied by EMD/BG at the rate of 20 per cent of FOB value.

(iv) The EMD/BG of an exporter who exports less than 95 per cent of the export entitlement in a particular period under FCFS, PPT, NQT, or during the revalidation period mentioned at para (iii) above for PPE including PPT, MEE, NOE including NQT or PSE shall be forfeited as hereinafter provided. The DG, AEPC shall forfeit the EMD/BG in case utilisation is upto 75 per cent in case of fast moving items and upto 50 per cent in case of slow moving items proportionate to the short-fall in utilisation. If utilisation of export entitlement allocation is less than the above, the EMD/BG shall be forfeited in full. For this purpose utilisation shall be computed on the basis of each system and each period separately. In case of extension of validity certification the percentage utilisation shall be computed separately for each certification validity extended.

(v) All forfeited EMD/BG shall be deposited into a P. D. account of Govt. to be operated in such manner as Govt. notifies from time to time.

(vi) Persons to whom export entitlements are allotted but who do not utilise them fully would render themselves liable to disqualification from getting entitlement in future without prejudice to any other action that may be taken against them.

(vii) All applications for extension shall be submitted complete in all respects before the expiry of the validity of the original entitlement.

#### 17. Appeal against Forfeiture of EMD/BG :

An exporter when aggrieved by an order of forfeiture by DG, AEPC under para 16(iv) above may appeal before the Textiles Commissioner, Bombay against such forfeiture within 15 days of receipt of such communication on forfeiture. The Textile Commissioner shall, upon receipt of the representation give

it ruling as early as possible. While disposing appeals, he may take into consideration force majeure conditions. He may also take into consideration the promptness in surrendering the unutilised entitlements during the validity of the entitlement. For this purpose the Textiles Commissioner shall mean and include such other officers as designated by him.

#### 18. Clearance by Customs

(a) Products under restraint including items not subject to specific limits in USA :—

Shipments will be allowed by Customs Authorities at the port of shipments after verifying the certification of export entitlement on the original and duplicate of shipping bills for individual consignments issued by the AEPC.

#### (b) Handloom Garments :—

In so far as exports to all handloom garments except tailored Collar Shirts corresponding to restrained items in Canada, Cotton handloom garments to Austria, special quantities reserved for handloom garments in some of the restrained categories to USA, EEC, Norway, Finland shipments will be permitted by the Customs on the basis of Inspection Endorsement by the Textile Committee in part 2 of the combination form.

#### (c) Garments falling under India items :—

In respect of India items which are traditional folklore handicraft textile products of India, shipments will be permitted by the Customs for exports to EEC, USA, Finland, Austria, Sweden, Norway, and Canada on the basis of appropriate certificates issued by the office of the Development commissioner (Handicrafts).

#### 19. (a) Export Certificate, Certificate of Origin and visa :—

The following certificates required under the relevant bilateral textile agreements will be issued by AEPC or any other agency duly authorised in this behalf :—

- (1) (a) Export Certificates and Certificate of origin for all garment/knitwear items under restraint.
- (b) Certificates of Origin for all non-restrained garments/knitwear items.
- (2) Finland—Export Certificates for restrained items.
- (3) Sweden—Export Certificates for restrained items.
- (4) Austria—Export Certificates for garments subject to restraint or surveillance.
- (5) Norway—Export Certificates and certificate of origin in respect of categories subject to specific limits.
- (6) Canada—Export Certificate for garment of knitted, powerloom and mill-made origin are subject to restraint except for consignments valued at Canadian \$ 500 or less.



(7) U.S.A.—Visa for all garment/knitwear consignments valued over US \$ 250.

(b) Handloom Certificate—

In the case of export of all handloom garments except Tailored Collar Shirts corresponding to restrained items to Canada, cotton handloom garments to Austria and special quantities reserved for Handloom Garments in some of the restrained categories to EEC, Norway and Finland the Textile Committee will issue the certificate as prescribed in the Bilateral Agreements for such products.

20. Government reserves the right to make amendments to any of the foregoing provisions without giving prior notice.

21. The addresses of the concerned Export Promotion Councils and the offices of the Textile Commissioner, Textile Committee and Development Commissioner (Handicrafts) are as follows :

1. The Apparel Export Promotion Council, Sahyog Building, 4th Floor, 58, Nehru Place, New Delhi-110019.
2. The wool and woollen Export Promotion Council, 612/714, Ashoka Estate, 24 Barakhamba Road, New Delhi.
3. Office of the Textile Commissioner, New CGO Complex, New Marine Lines, (Post Box No. 11500) Bombay 400020 Telephone No. 291229, 291050, Telex No. 011-2425 TXIND.
4. Textile Committee: "Crystal" 79, Dr. Anne Besant Road. Bombay-400018.
5. Development Commissioner (Handicrafts) West Block-VII R. K. Puram, New Delhi-110066

P. SHANKAR, Jt. Secy.

